डिजिटल महाशक्ति की ओर भारत

बजट 2026-27 में प्रस्तावित कर में छूट, भारत में वैश्विक क्लाउड और एआई अवसंरचना निवेश के लिए दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता प्रदान करता है। 2047 तक इस ढांचे का विस्तार करके, सरकार उच्च पूंजी-गहन और दीर्घ निवेश चक्र वाले इस क्षेत्र के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमेय वातावरण प्रदान करती है। साथ ही, यह नीति स्पष्ट पात्रता शर्तों और घरेलू संचालन पर निरंतर कराधान के माध्यम से संतुलन बनाए रखती है।

क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय में डिजिटल अवसंरचना की रीढ़ बन चुकी है। इसके माध्यम से दूरस्थ सर्वरों पर बड़े पैमाने पर डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और आदान-प्रदान संभव हो पाता है। इससे व्यवसायों, सरकारों और आम लोगों को बिना किसी भौतिक सिस्टम के, रियल टाइम में डिजिटल सेवाएं मिलती हैं। क्लाउड अवसंरचना की खास बात यह है कि यह लचीली और मापनीय होती है। इसी वजह से इसका उपयोग डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उन्नत क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ रहा है। क्लाउड सेवाओं के साथ डेटा सेंटर भी जुड़े होते हैं। ये डेटा सेंटर इन सेवाओं का आधार होते हैं, जहां सर्वर और नेटवर्किंग सिस्टम काम करते हैं। जैसे-जैसे डिजिटल गतिविधियां बढ़ रही हैं और एआई का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बड़े और आधुनिक डेटा सेंटरों की मांग भी तेज़ी से बढ़ी है।

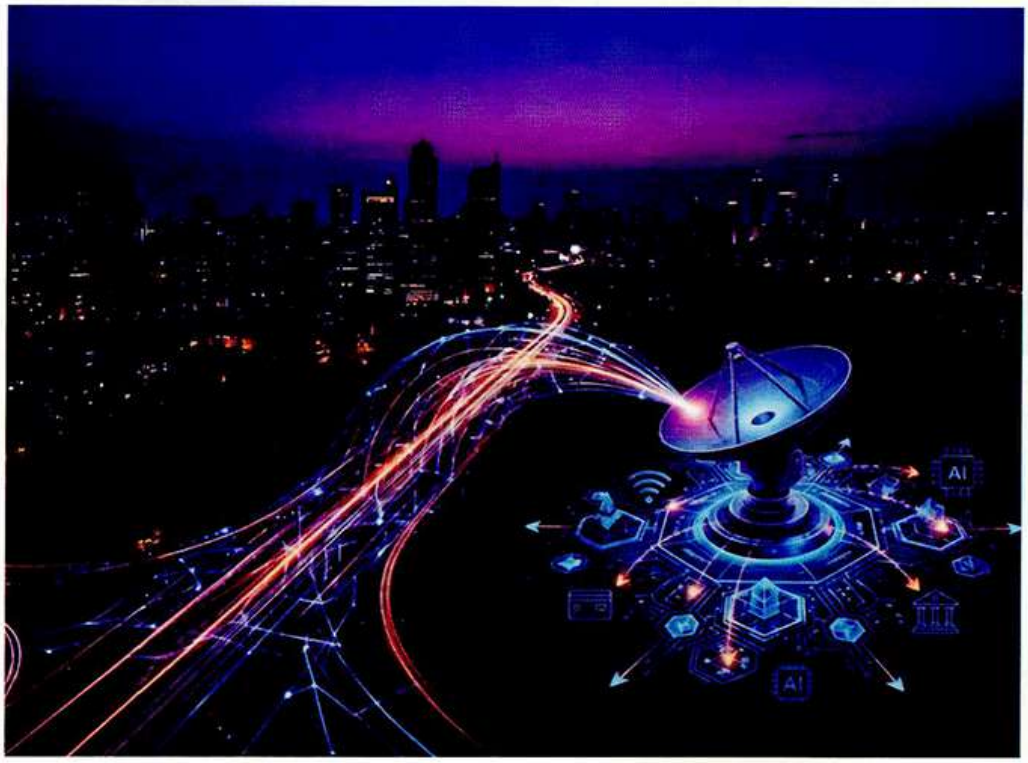

विशेषज्ञों के अनुसार, क्लाउड सेवा प्रदाता और डेटा सेंटर मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बनाते हैं। विश्व स्तरीय डेटा सेंटर बनाने के लिए भारी निवेश, आधुनिक तकनीक, विशेष कौशल और वैश्विक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। केवल घरेलू संसाधनों के भरोसे इस तेज़ी से बढ़ती मांग को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में विदेशी निवेश को आकर्षित करना ज़रूरी हो जाता है। इस संदर्भ में, विदेशी निवेश को आमंत्रित करना भारत को अवसंरचना निर्माण में तेज़ी लाने, वैश्विक डिजिटल मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत होने और इस रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण तथा तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाता है।

2047 तक कर में छूट का प्रस्ताव

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत भारत में डेटा सेंटरों के माध्यम से संचालन करने वाले पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए वर्ष 2047 तक कर में छूट का प्रस्ताव किया गया है। यह उपाय भारत की स्थिति को क्लाउड और एआई अवसंरचना के वैश्विक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदम है, साथ ही 2047 तक विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य का भी समर्थन करता है।

इस पहल के पीछे का तर्क डिजिटल अवसंरचना निवेशों की प्रकृति में निहित है। डेटा सेंटरों के लिए भारी पूंजी निवेश, लंबी विकास अवधि और स्थिर नीतिगत

परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक कर छूट प्रदान करके, सरकार वैश्विक क्लाउड प्रदाताओं को नीति-निश्चितता प्रदान करती है, जिससे उन्हें भारत में अपने संचालन स्थापित करने और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

नई कर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

- विदेशी क्लाउड कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ उनकी वैश्विक आय पर कर छूट मिलेगी।
- यह छूट तभी मिलेगी जब वे भारत में स्थित अनुमोदित डेटा सेंटर का उपयोग करेंगी।
- भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए घरेलू पुनर्विक्रेता का उपयोग करना होगा, जिससे कर व्यवस्था बनी रहे।
- 15 प्रतिशत का सुरक्षित लाभ मार्जिन तय किया गया है। इसका मतलब है कि भारतीय डेटा सेंटर कंपनी अपनी लागत पर 15 प्रतिशत लाभ घोषित कर सकती है।
- यह व्यवस्था कर संबंधी विवाद कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए की गई है।

व्यापक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंध

महत्त्वपूर्ण रूप से, यह कर नीति एक पृथक उपाय नहीं है। यह बजट 2026-27 में भारत के प्रौद्योगिकी और डिजिटल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए व्यापक पहल के समूह का हिस्सा है। ये उपाय प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों जैसे सेमीकंडक्टर उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से लेकर आईटी सेवाओं और डिजिटल अवसंरचना तक आदि को संबोधित करते हैं।

एक प्रमुख घटक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का विस्तार है, जो घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताओं को विकसित करने के पूर्व प्रयासों पर आधारित है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर उपकरणों के डिज़ाइन और निर्माण, महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के उत्पादन, डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और कुशल प्रतिभा के विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो उन्नत कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर अवसंरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स आधार को सुदृढ़ करता है।

इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को भी महत्त्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जिसका आवंटन लगभग ₹22,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया है। 149 आवेदनों के माध्यम से उद्योग की मज़बूत भागीदारी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। यह विस्तार आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने और आयात निर्भरता को कम करने में सहायक होगा।

आईटी सेवाओं में सुधार

बजट में आईटी सेवा क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जो भारत के सबसे बड़े निर्यात उद्योगों में से एक है, जिसका निर्यात 220 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कर-निश्चितता और

व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए, विभिन्न आईटी-संबंधित सेवाओं जैसे सॉफ्टवेयर विकास, आईटी-सक्षम सेवाएं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और अनुबंध अनुसंधान एवं विकास आदि को एकल श्रेणी 'सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं' के अंतर्गत समाहित किया गया है।

15.5 प्रतिशत का एक समान सुरक्षित बंदरगाह मार्जिन प्रस्तावित किया गया है, साथ ही पात्रता सीमा को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अनुमोदनों को स्वचालित, नियम-आधारित प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किया जाएगा और एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) तंत्र को तेज़ किया जाएगा, जिससे अनुपालन भार और विवादों में कमी आएगी।

भारत का विस्तारित डिजिटल अवसंरचना आधार

भारत का क्लाउड और डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ती डिजिटल स्वीकार्यता के साथ तेज़ी से विस्तार कर रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने जीआई क्लाउड (मेघराज) की स्थापना की है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए सुरक्षित और स्केलेबल क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय डेटा केंद्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बहु-स्तरीय सुरक्षा ढांचे के साथ संचालित होते हैं।

उद्योग अनुमानों के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1,280 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और 2030 तक इसके चार से पांच गुना बढ़ने का अनुमान है। यह वृद्धि डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग, इंटरनेट प्रसार और विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित अनुप्रयोगों के विस्तार से प्रेरित है।

साथ ही, इस क्षेत्र में निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत के डेटा सेंटर उद्योग में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले ही किया जा चुका है, जबकि अतिरिक्त 90 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं घोषित की गई हैं।

वैश्विक नीतिगत परिप्रेक्ष्य

भारत की नीतिगत दृष्टि को वैश्विक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एआई और डेटा सेंटर अवसंरचना के विकास को नियामक और वित्तीय उपायों के माध्यम से सक्रिय रूप से समर्थन दे रही हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर परियोजनाओं को गति देने के लिए नीतिगत पहल शुरू की हैं, जिनमें त्वरित स्वीकृतियां, सार्वजनिक भूमि का उपयोग और लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। इसी प्रकार, चीन में भी एआई और क्लाउड अवसंरचना का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जिसे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े निवेश का समर्थन प्राप्त है। ये विकास एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। डिजिटल अवसंरचना, विशेष रूप से एआई-सक्षम डेटा सेंटर, अब एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखे जा रहे हैं।

निष्कर्ष

बजट 2026-27 में प्रस्तावित कर में छूट, भारत में वैश्विक क्लाउड और एआई अवसंरचना निवेश के लिए दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता प्रदान करता है। 2047 तक इस ढांचे का विस्तार करके, सरकार उच्च पूंजी-गहन और दीर्घ निवेश चक्र वाले इस क्षेत्र के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमेय वातावरण प्रदान करती है। साथ ही, यह नीति स्पष्ट पात्रता शर्तों और घरेलू संचालन पर निरंतर कराधान के माध्यम से संतुलन बनाए रखती है। सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और आईटी सेवा सुधारों के साथ मिलकर, यह भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की एक समन्वित रणनीति को दर्शाती है। तेज़ी से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, यह दृष्टिकोण भारत को क्लाउड और डेटा सेंटर निवेश के लिए एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक गंतव्य के रूप में स्थापित करता है तथा एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की उसकी व्यापक महत्त्वाकांक्षा को समर्थन देता है। ❑

(पसूका से प्राप्त जानकारी के आधार पर रोज़गार समाचार टीम द्वारा संकलित लेख)